ment of cancer has been developed indigenously by the Department of Electronics and installed and successfully put to test at the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh; and

(b) if so, what are the salient features thereof; and how it compares with the equipment hitherto imported for use in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M.G.K.MENON) : (a) Yes, Sir. A Linear Accelerator machine for Cancer Therapy was developed jointly by the Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (Bombay), Central Scientific Instruments Organisation (Chandigarh) and Post Graduate Institute of Medical Education and Research (Chandigarh) with funding from Department of Electronics. This equipment has been installed at Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh where it is being successfully put to use for treatment of patients.

(b) The main specifications of the machine are comparable with similar imported machines. It operates in the nominal energy range of 4 Mev and has a operational dose rate of 250 Rads/minute at an Isocentre to target distance of 100 cms. The maximum field size for treatment is 26 x 26 cm.

Closure of sole public sector units

394. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a study made by the Ministry of Finance has recommended closing down of some public sector units ;

(b) if so, what are the names of such public sector units which are continuously incurring losses; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

दिल्ली में जल तथा वायु प्रदूषण के संबंध में प्राप्त शिकायतें

*395. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों के दौरान सरकार को दिल्ली में जल तथा वायु प्रदूषण के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ; और

(ख) इनमें से कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : सरकार को जनवरी-अप्रैल, 1990 के बीच दिल्ली में जल और वायु प्रदूषण के संबंध में 41 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) प्राप्त हुई 41 शिकायतों में से, 24 यूनिटों का निरीक्षण कर लिया गया है और 17 यूनिटों का निरीक्षण अभी किया जाना है। दिल्ली प्रशासन की छः यूनिटों को अनुकूल औद्योगिक क्षेत्रों में शिफ्ट करने की सलाह दी गई है। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत तीन इकाइयों को नोटिस जारी कर दिये गये हैं। वायु (प्रदूषण निवारण एवं

नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत 5 यूनिटों को नोटिस जारी किये गये हैं । एक यूनिट को दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है । एक यूनिट को कोयले के स्थान पर द्रव्य पेट्रोलियम गैस या बिजली जैसे गैर-प्रदूषक इंधन का प्रयोग करने का निदेश दिया गया है । पांच अन्य यूनिटों में भी निरीक्षण किया गया है और उन्हें नोटिस जारी किये जा रहे हैं । तीन यूनिटों को निरीक्षण के दौरान बन्द पाया गया ।

राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन

*396. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से यह कहने का निश्चय किया है कि वे केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990–95) को तैयार करने के सिलसिले में सभी योजना स्कीमों की, जिनमें केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित स्कीमें भी शामिल हैं, समीक्षा की जा रही है । राज्य सरकारों, को केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित उन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जानी हैं, उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जायेंगे ।

तट रक्षक परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*397. **श्री राम नरेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को तट रक्षक परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ और उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है, यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) सरकार ने रक्षा मंत्रालय के दिनांक 10 मार्च, 1986 के संकल्प संख्या 1975/एस/रक्षा/सचि/86 के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में तट रक्षक सलाहकार समिति का गठन किया है जिसमें रक्षा गृह, वित्त (राजस्व विभाग), विधि,, कृषि, विदेश और भू-तल परिवहन मंत्रालयों और महासागर विकास और पर्यावरण विभागों, नौसेना और तट रक्षक संगठन के प्रतिनिधि शामिल हैं इस समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए :—

(एक) उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना ।

(दो) इन कार्यों में लगी एजेंसियों की विविधता को समाप्त करना और बेहतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना ।

(तीन) तट रक्षक संगठन तथा नौसेना, सीमा शुल्क, महासागर विकास विभाग और पर्यावरण विभाग तथा अन्य समुद्री एवं अर्ध सैनिक संगठनों के परस्पर कार्यों और क्षेत्राधिकार (कार्यात्मक और भौगोलिक) को पुनः निर्धारित करना ।

2. समिति को निम्नलिखित पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देनी थीं :—

(एक) भौतिक और कार्यात्मक दोनों तरह के क्षेत्राधिकार सही-सही निर्धारण